



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या—cm-306
21/07/2017

**वज्रपात की पूर्व जानकारी की तकनीक आपदा
प्रबंधन विभाग जल्द से जल्द लाये, खर्च मुख्यमंत्री
राहत कोष उठायेगा :- मुख्यमंत्री**

पटना, 21 जुलाई 2017 :- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज अधिवेशन भवन में बिहार राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच 2017 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुये कहा कि इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का अभिनन्दन करता हूँ। उन्होंने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य 2015 में हुये जापान के सेंडई कॉन्फ्रेंस के बाद प्रारंभ हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार में भी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात डिजास्टर मैनेजमेंट का रोडमैप तैयार किया गया, जिसे बिहार सरकार ने स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि रोडमैप पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में भी विस्तृत चर्चा की गयी तथा सभी विभागों के लिये कार्ययोजना बनायी गयी तथा उनके कर्तव्य निर्धारित किये गये। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता है। आपदा से जान-माल का नुकसान होता है। यह नुकसान कम से कम हो, हमारा यही लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हमें यह लक्ष्य बनाना चाहिये कि हम कैसे आपदा के प्रभाव को कम कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार बहु आपदा से प्रभावित राज्य है। बिहार में विचित्र स्थिति है। बिहार बाढ़ और सुखाड़ दोनों से प्रभावित होता है। यहाँ वर्षा कम हो फिर भी राज्य से जुड़े अन्य क्षेत्रों में हो रही वर्षा से बिहार प्रभावित होता है। अगर नेपाल में भारी वर्षा हुयी तो नेपाल से निकलने वाली नदियों के पानी में उफान आयेगा। अगर मध्यप्रदेश एवं झारखण्ड में अधिक वर्षा हुयी तो दक्षिण बिहार में बाढ़ की स्थिति बन जायेगी। अगर उत्तराखण्ड में अधिक वर्षा हुयी तो गंगा के पानी में उफान आ सकता है। उन्होंने कहा कि हमें बाढ़ और सुखाड़ दोनों से लड़ने के लिये हर वर्ष तैयार रहना पड़ता है। हम हर स्थिति का मुकाबला करने के लिये तैयार हैं, इसके लिये लोगों तथा अधिकारियों को तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों को तत्काल सहायता देने के कार्य की शुरुआत की गयी। कोसी त्रासदी के एक वर्ष पूर्व 2007 में बिहार में बड़ी बाढ़ आयी। बाढ़ से 22 जिले तथा 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हुये थे। लोगों को राहत पहुँचाया गया, आपदा प्रबंधन का कार्य किया गया। राहत कार्य के दौरान कई चीजें सामने आयी। जैसे पहले कहा जाता था कि हमारे यहाँ छोटे एवं सीमान्त किसान 86 प्रतिशत हैं परन्तु राहत वितरण के दौरान पता चला कि उनकी संख्या लगभग 96 प्रतिशत है। उसी समय यह तय किया गया कि सब चीजों के लिये मापदण्ड बनायेंगे। किस स्थिति में क्या करना है, इसके लिये एस0ओ0पी0 बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र स्तर पर गुजरात के भूकंप हादसा तथा ओडिशा में आये साइक्लोन के बाद आपदा प्रबंधन के विषय में चर्चा होने लगी कि सिर्फ राहत कार्य से काम नहीं चलेगा। कोसी त्रासदी का उदाहरण देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि 2008 में कोसी त्रासदी हुयी थी। 18 अगस्त को नेपाल में कोसी नदी पर बना बांध टूट गया था। उस वक्त हम नेपाल जाकर पूरे चीज को देखना चाहते थे परन्तु इसकी इजाजत नहीं मिली। 20 अगस्त को हमने स्टेट

हेलिकॉप्टर से कोसी नदी को देखा। उन्होंने कहा कि कोसी नदी में गाद काफी जमा हो गया था, जिस कारण कोसी नदी का बेस काफी ऊपर उठ गया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद 15 दिनों तक निरंतर मेहनत हुआ, लोगों को राहत पहुँचाई गयी। पहली बार इतने बड़े स्तर पर राहत शिविर बनाया गया। हम स्पॉट पर जाकर लोगों से बात करते थे, उनकी शिकायत भी सुनते थे। राहत शिविरों में लोगों के लिये कपड़ा, बर्तन, महिला एवं पुरुषों के लिये अलग-अलग शौचालय आदि की व्यवस्था की गयी थी। हमने खुद एक-एक चीज को देखा था, हम सभी राहत शिविरों में गये थे। उन्होंने कहा कि यही आधार बना हमारे एस0ओ0पी0 का। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोसी त्रासदी के दौरान हमने देखा कि लोगों को राहत पहुँचाने का दावा करने वाले लोग लोगों के बीच पुराना कपड़ा राहत शिविरों में बांट रहे थे। हमने उसी वक्त यह मना कर दिया। सरकारी राहत शिविरों में बाहर का आदमी आकर कुछ नहीं बांट सकता है क्योंकि इन शिविरों में जो भी जरूरत हो, हम सब पूरा कर रहे थे। इस पृष्ठभूमि में एस0ओ0पी0 बनाया गया। वज्रपात के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के कारण अगर मृत्यु होती है तो 24 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये की राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि वज्रपात का पहले पता नहीं चल सकता है। हमने इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया तो पता चला कि आन्ध्रप्रदेश में इस तरह का काम हो रहा है। वज्रपात के तीस मिनट पूर्व उससे संबंधित जानकारी मिल जाती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस तकनीक को बिहार में लाइये और उसे लागू कीजिये। अगर वज्रपात से पूर्व उसकी जानकारी मिल जाती है तो उस क्षेत्र के लोगों को सचेत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तत्काल इस तकनीक को बिहार में लाइये, देर नहीं कीजिये, पूरा नेटवर्क तैयार कीजिये। तकनीक को बिहार लाने में जो भी पैसा लगेगा, वह मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में बिहार में वज्रपात की घटनायें बढ़ गयी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल के बच्चों को भूकम्प एवं आग जैसी चीजों के बारे में संवेदनशील बनाया जा रहा है। आपदा की स्थिति में कैसे बचाव किया जाय, इसकी उन्हें जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ठीक से हमारे स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित कर दिया जाय तो वे जुड़े अन्य लोगों को भी इसके बारे में बतायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 2.5 करोड़ स्कूली बच्चें हैं। अगर उन्हें प्रशिक्षित कर दिया जाता है तो कितना बड़ा काम होगा। आपदा के प्रभाव में कितनी कमी आयेगी। अगलगी के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष अप्रैल माह में बिहार में अगलगी की अभूतपूर्व घटनायें घटी। जब इस संदर्भ में जानकारी ली गयी तो पता चला कि ज्यादातर अगलगी की घटनायें 11 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न के बीच होती है, जिसका मुख्य कारण खाना बनाना था। लोगों के लिये इस संदर्भ में सरकार द्वारा एक एडवाइजरी जारी किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा उत्तरदायित्व आमलोगों के प्रति है। हम हमेशा उनकी सुविधा एवं बेहतरी के लिये काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण ऐसी चीज है, जिसका आभास सभी लोगों के मन में होना चाहिये। हो रहे सड़क हादसे के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में ब्लैक स्पॉट का सर्वे कराया जा रहा है। नाव हादसे के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रायः देखा जाता है कि नाव पर ज्यादा संख्या में लोग सवार हो जाते हैं। लोगों के साथ-साथ जानवरों को भी नाव पर लाद दिया जाता है। सूर्य ढलने के बाद भी नाव का परिचालन होता है। लोगों को इसके बारे में समझाना होगा, नावों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। सूर्य ढलने के बाद नावों का परिचालन नहीं होना चाहिये। लोगों को सजग करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजास्टर रोडमैप के क्रियान्वयन में जन-जन को शामिल करना होगा। हर क्षेत्र में कोई न कोई आपदा का खतरा है, खतरों के बारे में सोच विकसित करने, उसका नुकसान कम से कम हो, इन सबको ध्यान में रखते हुये 15 साल के लिये

आपदा रोडमैप बनाया गया है। उसी के वर्षगांठ के अवसर पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैंने शुरू में ही कहा था कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार होता है। हमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिये। इसमें कोताही नहीं बरतिये, नहीं तो अन्तरात्मा को कष्ट होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में देश-विदेश के विशेषज्ञ आये हैं। विशेषज्ञों के बीच सार्थक चर्चा होगी, उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे।

बिहार राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच 2017 के अवसर पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन के पारंपरिक ज्ञान पर लिखित पुस्तक 'धरोहर' का विमोचन किया तथा संबल एप्प का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पतंगोत्सव के दिन घटित भीषण नाव दुर्घटना में उत्कृष्ट बचाव कार्य करने के लिये श्री राजेन्द्र सहनी, श्री आशुतोष कुमार, श्री संदीप सहनी, श्री सोनू सहनी, श्री जामुन सहनी, श्री पंकज कुमार को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री को पौधा भेंट किया गया।

इस अवसर पर आयोजित समारोह को आपदा प्रबंधन मंत्री श्री चन्द्रशेखर, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ब्यासजी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ० उदय कान्त मिश्रा, प्रबंध निदेशक आई०सी०आई०एम०ओ०डी० डॉ० डेविड मोल्डेन, बिहार प्रमुख यूनिसेफ श्री एम० असादुर्रहमान, मिलिंडा गेट्स फाउण्डेशन की वैलेरी विमो ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन श्री प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव सहित अन्य वरीय अधिकारी, समारोह में देश-विदेश से आये विशेषज्ञ एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
